# LOK SABHA DEBATES

**(Part I — Proceedings with Questions and Answers)**

***The House met at Eleven of the Clock***

**Friday, August 01, 2025 / Sravana 10, 1947 (Saka)**

## HON'BLE SPEAKER

**Shri Om Birla**

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

# LOK SABHA DEBATES

## PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

**Friday, August 01, 2025 / Sravana 10, 1947 (Saka)**

**CONTENTS** **PAGES**


… 1 – 30

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31 – 50
(S.Q. NO. 181 – 200)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 2071 – 2300)

# LOK SABHA DEBATES

**(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)**

**Friday, August 1, 2025 / Sravana 10, 1947 (Saka)**

# LOK SABHA DEBATES

## PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

*Friday, August 1, 2025 / Sravana 10, 1947 (Saka)*

**C ON T E N T S** **P A G E S**


**RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION** 281

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 281 - 83

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 137TH AND 150TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE – LAID** 284

Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav

**BUSINESS OF THE HOUSE** 284 - 85

**MATTERS UNDER RULE 377 – LAID** 286 - 97

Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar 286

Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya 286

Shri Praveen Patel 287

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 287

Shri Godam Nagesh 288

Shrimati Aparajita Sarangi 288

Dr. K. Sudhakar 289

Shri Yogender Chandolia 289

Shri Janardan Mishra 290

Shri Bibhu Prasad Tarai 290

Shri Kota Srinivasa Poojary 291

Shri Anoop Pradhan Valmiki 291

Dr. Namdeo Kirsan 292

**Dr. Shivaji Bandappa Kalge** **292**

**Shri Hibi Eden** **293**

**Shri Shafi Parambil** **293**

**Shri Brijendra Singh Ola** **294**

**Shri Krishna Prasad Tenneti** **294**

**Shri Sanjay Dina Patil** **295**

**Shri Balashowry Vallabhaneni** **295**

**Shri Chandra Prakash Choudhary** **296**

**Shri Vishaldada Prakashbapu Patil** **296**

**Shri Zia Ur Rehman** **297**

**…** **298 - 99**

(1100/ANK/RP)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न काल।

क्वेश्चन नंबर-181, श्रीमती लवली आनंद।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप सदन की गरिमा को बनाए रखें।

… (व्यवधान)

1101 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। यह माननीय सदस्यों का हक और अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी और तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह आपका गलत तरीका है, गलत आचरण और गलत व्यवहार है। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या आपको यह करना उचित लगता है?

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आपको संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आएं, नारेबाजी करें, यह उचित नहीं है। यदि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो प्रश्न को उठाने देना पड़ेगा। इससे सरकार की जवाबदेही तय होगी।

… (व्यवधान)

(pp. 2-30)

**माननीय अध्यक्ष :** बालू जी, क्या आप माननीय सदस्यों को बैठने का इशारा कर रहे हैं? माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे हमेशा आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्यवाही को चलने दें। माननीय सदस्यों को प्रश्न काल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप अपनी बात को कहें।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने, अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया है। इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी करके और तख्तियां लहराकर मत गंवाइए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप बैठिए। मैंने पहले भी कहा था यदि आप तख्तियां लेकर आएंगे और नारेबाजी करेंगे, तो सदन नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1103 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/RAJ/RTU)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

## स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

1400 बजे

(इस समय अभय कुमार सिन्हा, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

**माननीय सभापति :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नम्बर 2, श्री प्रतापराव जाधव जी।

… (व्यवधान)

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) :** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**----**

**माननीय सभापति :** आईटम नम्बर 3, श्री शान्तनु ठाकुर जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I rise to present a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021:-

(1) The Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 346(E) in Gazette of India dated 28th May, 2025.

(2) The Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 347(E) in Gazette of India dated 28th May, 2025.

(3) The Inland Vessels (Life Saving Appliances) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 349(E) in Gazette of India dated 28th May, 2025.

(4) The Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Amendment Rules,

2025 published in Notification No. G.S.R. 350(E) in Gazette of India dated 28th May, 2025.

(5) The Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 348(E) in Gazette of India dated 28th May, 2025.

---

**माननीय सभापति :** आईटम नम्बर 4, श्री संजय सेठ जी।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Land Warfare Studies, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Land Warfare Studies, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) A copy of the Works of Defence Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O.4(E) in Gazette of India dated 3rd April, 2025 under sub-section (3) of Section 44 of the Works of Defence Act, 1903.

(3) A copy of the Inter-services Organizations (Command, Control and Discipline) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O.10(E) in Gazette of India dated 27th May, 2025 under Section 15 of the Inter-services Organizations (Command, Control and Discipline) Act, 2023. …(व्यवधान)

---

**माननीय सभापति :** आईटम नम्बर 5 , श्री प्रतापराव जाधव जी।

… (व्यवधान)

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 137वें और 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) :** आदरणीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित "वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और महामारी कोविड-19 का शमन' विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 137वें और 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।...(व्यवधान)

---

**माननीय सभापति :** आईटम नम्बर 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 4th of August, 2025, will inter-alia consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper :- [ it contains - (i) Further consideration and passing of the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024; (ii) Consideration and passing of the Merchant Shipping Bill, 2024; and (iii) Consideration and passing of the Indian Ports Bill, 2025].
2. Consideration and passing of the following Bills:-
   (i) The National Sports Governance Bill, 2025; and
   (ii) The National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025

3. Statutory Resolution seeking disapproval of the Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (No. 1 of 2025) promulgated by the President of India on the 9th of June, 2025 and consideration and passing of the Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025.
4. Discussion and voting on Demands for Grants (Manipur) for the year 2025-26 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill, *after presentation of concerned Demands for Grants.*

---

(1405/NK/UB)

**माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) :** माननीय सदस्यगण, हम आपको कई बार बता चुके हैं, आप ऐसे तख्तियां लेकर नहीं आ सकते हैं। इस सभा की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कृपया आप ऐसे तख्तियाँ लेकर वेल में न आएं। यह हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have requested you several times not to bring placards in the House like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: In spite of repeated requests, you are not listening. You are not cooperating.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We have lost a lot of precious time during the last two weeks.

… (*Interruptions*)

## नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1406 बजे

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

## Re: Need to provide adequate funds to improve facilities in Government schools in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency

**श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) :** मेरे संसदीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के सरकारी स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि बच्चों को उचित शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है और ना ही स्कॉलरशिप दी जा रही है। अधिकांश स्कूलों में शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, और जहाँ हैं भी, वहाँ उनकी साफ-सफाई अत्यंत खराब है। क्लास रूम में बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क नहीं हैं, जिससे बच्चों को फर्श पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण मौजूदा शिक्षकों पर काम का अत्यधिक बोझ है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कक्षाओं में सफाई का स्तर अत्यंत निम्न है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई क्लास रूम में ब्लैकबोर्ड तक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे शिक्षकों को पढ़ाने में और बच्चों को समझने में भारी परेशानी होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह तत्काल इस मामले का संज्ञान ले और मेरे संसदीय क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए और तत्काल स्कूलों में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। (इति)

## Re: Improvement of NH-48 passing through Himmatnagar in Sabarkantha Parliamentary Constituency

**श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) :** मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे लोकसभा साबरकांठा के हिम्मतनगर नगर क्षेत्र से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (NH-48), जो कि चेनेज 491040 से 494307 तक विस्तृत है, वर्तमान में तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा बढ़ते यातायात दबाव के कारण अव्यवस्थित होता जा रहा है। इस खंड पर सेवा मार्ग एवं जल निकासी हेतु 7 मीटर चौड़ी RCC संरचना स्वीकृत है, किंतु वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में यह अपूर्ण एवं अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण किया जाए:-

1. NH-48 के उल्लिखित खंड में सेवा मार्ग को 7 मीटर से बढ़ाकर 9 मीटर चौड़ा किए जाने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए।
2. जल निकासी हेतु Precast Factory Made RCC Drain System को अनुमोदित किया जाए।
3. वर्षाजल को हटमाती नहर में प्रवाहित करने हेतु एक सुनियोजित एवं समर्पित जल निकासी योजना तैयार की जाए।
4. यह अवगत कराना समीचीन होगा कि 45 मीटर का अतिरिक्त ROW (Right of Way) स्थानीय निकाय (नगरपालिका) से उपलब्ध है, जिसे इस उद्देश्य हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।

(इति)

## Re: Need to extend benefit of Central Government Schemes to give impetus to industrial development in Phulpur Parliamentary Constituency

**श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) :** मैं माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी का ध्यान फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उचित ढांचागत सुविधाओं के अभाव में इन संभावनाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने पर विचार किया जाए: - (1) Industrial Corridor Development Programme (NICDP.) (2) Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP). (3) Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (MIIUS). (4) Special Economic Zones (SEZs) इन योजनाओं के माध्यम से फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अतः, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करें।

(इति)

## Re: Need to enhance the amount of honorarium of Anganwadi workers

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) :** देश के ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंन्द्रों में जो सेविकाएं एवं सहायिकाएं कार्यरत हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे बच्चों को शिक्षा देने, छोटे बच्चों को रोगों से बचाने के लिए बच्चों को पोषणाहार संबंधी सुझाव देने एवं गांव की महिलाओं के बीमार होने पर सहायता एवं ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रधान करती हैं। सेविका और सहायिका दिन के अलावा रात में सर्दी और बरसात में भी कार्य करती हैं। इन आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविकाओं एवं सहायिकाओं को उनके कार्यों के अनुपात में पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनको दिए जाने वाला मानदेय आज की महंगाई के समय बहुत ही अपर्याप्त है। इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविकाओं एवं सहायिकाओं को बढ़ती महंगाई के कारण एवं इनके द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे सहयोग और सहायता के लिए उनका मानदेय बढ़ाया जाए।

(इति)

**Re: Establishment of Jawahar Navodaya Vidyalaya in Adilabad Parliamentary Constituency**

SHRI GODAM NAGESH (ADILABAD): Adilabad District confronts significant challenges in providing quality education, resulting in a literacy rate of 63.46%, which is below the national average. Consequently, in my Adilabad Parliamentary Constituency our students often face difficulties in meeting the standards of central curricula. Jawahar Navodaya Vidyalayas are esteemed institutions under the Ministry of Education, Government of India, designed to offer quality education to rural and tribal students. Establishing a JNV in Adilabad would provide access to a curriculum that aligns with national standards, fostering academic excellence. Residential setup that promotes all-round growth, including extracurricular activities and life skills. The District Administration has demonstrated a strong commitment to this initiative, offering allocation of suitable land and temporary infrastructure to facilitate the establishment of the school. Assistance in the construction of permanent school buildings upon approval. Therefore, I request the Government to kindly sanction JNV at Adilabad. (ends)

**Re: Need to strengthen primary and digital healthcare services in Urban and peri-urban slums in Bhubaneshwar, Odisha**

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I wish to raise the urgent need to strengthen primary and digital health access in the urban and peri-urban slums of Bhubaneswar. Rapid in-migration has expanded informal settlements in areas such as Salia Sahi, Jharpada belt, and Dumduma, where residents rely on seasonal water sources and informal providers. As per NFHS-5 (Odisha), anemia among women (15–49) is 64%, and child stunting remains high in low-income wards. Yet utilisation of eSanjeevani tele-medicine and Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) health IDs remains limited; local ASHA and Anganwadi workers report connectivity and awareness gaps. Under Article 21 (Right to Life), Article 47 (public health), and DPSP Article 39(e) (protection of health), scalable service delivery is required. With Union allocations State health outreach through Biju Swasthya Kalyan Yojana, Bhubaneswar can serve as a model. I request that the Government should come forward to establish Urban Health & Wellness Centres in slum clusters linked to AIIMS Bhubaneswar e-consult grids; expand community Wi-Fi health points for eSanjeevani usage; train SHG women as Digital Health Sakhis to generate ABHA IDs; integrate nutritional screening and anemia drives with school mid-day meal supply chains; and pilot heat-health surveillance during peak summer in partnership with ICMR.

(ends)

## Re: Shortage of fertilizers in Karnataka

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Karnataka is experiencing a critical shortage of essential fertilizers—especially Di-ammonium Phosphate (DAP)—amid the peak of the kharif season. China's abrupt reduction in DAP exports, driven by political considerations and domestic industrial demands, has disrupted India's supply chain. In Karnataka, the centre allocated 400,000 tonnes of DAP for the kharif season, but only 189,000 tonnes have been delivered. The State also relies on about 76,000 tonnes of carry-over stock, leaving many farmers undersupplied. Adding to this is the onset of early monsoons which have initiated the agricultural season earlier than usual. There are reports of hoarding by private traders and cooperatives and price-gouging have surfaced. This puts the farmers in a very difficult situation at the mercy of these hoarders who charge hefty premiums for fertilizers. I request the Government of India to urgently intervene, by ensuring that adequate stocks of fertilizers are available for our farmers and Karnataka receives another bountiful harvest this season.

(ends)

## Re: Non-extension of cashless medical facilities to pensioners of Electricity Distribution Companies in Delhi

**श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :** मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित किए जाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। विद्युत मंत्रालय, दिल्ली सरकार ने सभी DISCOM कम्पनियों को यह निर्देश दिए कि सभी पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा तुरंत दी जाए परंतु सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कॉम्पनियाँ जिनके मैं नाम ले रहा हूँ बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जैसी निजी बिजली वितरण कंपनियाँ इन पेंशनभोगियों को कैशलेस या प्रतिपूर्ति चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान नहीं कर रही हैं जबकि डीटीएल और आईपीजीसीएल जैसी सरकारी संस्थाओं ने मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया है, लेकिन इन निजी कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है। यह इन कंपनियों द्वारा वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों के साथ अन्याय है और दुखद है उनको इस उम्र मे इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले में जिन कम्पनियों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया हैं उन पर पेनल्टी के साथ उचित कारवाही हो, इसके साथ सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर न्याय हो, ताकि इन पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकें जिनके वे हकदार हैं। (इति)

## Re: Need to establish a Navodaya Vidyalaya or PM Shree School in Mauganj district, Madhya Pradesh

**श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) :** रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है | मऊगंज जिले की लगभग सम्पूर्ण आबादी सुदूर जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है | शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ट विद्यालय नहीं है | मऊगंज जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है | अत: माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय या पीएम श्री विद्यालय स्थापित किये जाने का कष्ट करे |

(इति)

## Re: Need to ensure healthcare services to all the employees including contractual workers of Paradip Port Authority through Paradip Port Authority Hospital

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Paradip Port Authority Hospital is an accredited and certified 64 bedded general hospital established by the PPA. The hospital has in-house specialty facilities available in the multi-disciplinary wings. Along with this, the hospital has been providing services to the employees (of certain categories) by specialists visiting as part-time consultants. However, the PPA hospital provides services to only regular employees of the port. The contractual workers, who are earning less than Rs. 21,000 per month, the other service providers and the daily wage workers from the locality are deprived of availing the health facilities from the port hospital. Having been equipped with advanced medical equipment and adequate health professional, it seems that the services of the hospital have been grossly underutilized. Hence, I would like to draw the attention of the hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways to look into the matter and instruct the port authority and hospital administration to provide health services to the entire community of workers of the port along with the people from the locality for the greater interest of the people of Paradip in my Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur, Odisha.

(ends)

**Re: Need to establish a National Environmental Management and Research Centre in Kudremukh township, Karnataka**

SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY (UDUPI CHIKMAGALUR): Kudremukh is nestled in the heart of the western ghats in Chikkamagaluru district. It is situated at an altitude of 6,207 ft and is the 3rd highest peak of Karnataka after Mullayyangiri, Baba Budangiri. This Industrial-cum-Mining Township is now tucked into the Kudremukh National Park. Kudremukh Park is a breathtaking destination known for its rich biodiversity and natural beauty, located in the Western Ghats of Karnataka. This place was a Mining operational area under the Kudremukh Iron Ore Corporation Limited (KIOCL) and now, after the Order of the Hon'ble Supreme Court, led to closure of the mining operation in this area. Currently, the available infrastructure such as laboratory operatable buildings, office premises, furniture, staff quarters, playground, bungalows, guest house, auditoriums, training centre, helipad are kept vacant and detoriating/collapsing gradually. The 10th suggestion of the National Forest Policy, 1988, also promotes forest education, research and extension, among other suggestions. Therefore, in this region, I think this Township is suitable for establishing a National Environmental Management and Research Centre. The results of the Research Centre's findings will benefit mankind and also in conservation prospects. I urge the Hon'ble Minister to establish this Research Centre in Kudremukh as early as possible.

(ends)

**Re: Need to restore stoppage of 'Bandikui-Bareilly Passenger' and 'Dehradun- Subedarganj Link Express' at Hathras Railway Station, Uttar Pradesh**

**श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि (हाथरस) :** मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि हाथरस में कोरोना काल से पहले रेल सेवा बांदीकुई-बरेली पैसेजर व देहरादून से सूबेदारगंज लिंक एक्सप्रेस का ठहराव होता था यह आज तक पुनः चालू नही हो पायी जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ,इन रेलगाड़ियों के पुनः ठहराव कराये जाने की कृपा करें।

(इति)

**Re: Alleged irregularities in implementation of Skill India Mission**

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Skill India aims to address the growing skill gap in India by providing vocational training and creating employment opportunities, which is a valuable goal. But unfortunately there have been reports of alleged misuse of funds and irregularities in certain implementations of the Skill India scheme & concerns regarding quality control, lack of proper monitoring, and instances of fraudulent training centers have come to notice. From the view point of quality issues, it is stated that some training centers have been accused of providing sub-par training, leading to concerns about the quality of skills imparted. With regard to misuse of funds, investigations have revealed instances of funds allocated to Skill India schemes being misappropriated by certain training providers. Further lack of monitoring has been noticed as inadequate oversight mechanisms have been pointed out, potentially allowing for fraudulent activities to go undetected. Implementation challenges are there since reaching geographically remote areas and ensuring effective training delivery is a challenge.

(ends)

**Re: Need to expedite completion of the doubling of Latur Road - Kurduwadi Railway Line Project in Maharashtra**

DR. SHIVAJI BANDAPPA KALGE (LATUR): I would like to draw the attention of the Hon'ble Railway Minister to the desperate need for doubling the Latur Road- Kurduwadi Railway Line under Solapur Railway Division of Central Railway in Maharashtra State. The survey for upgrading this strategic Railway infrastructure via Osmanabad and Latur has already been taken up in 2021 followed by collection of critical field data , and completion of the Survey Report. The importance of this Railway Project can be gauged with the aspect that the Hon'ble Prime Minister had inaugurated electrification of 186 km Kurduwadi-Latur Road Railway Rail Section, and 3rd and 4th railway lines of 25 km connecting Jalgaon to Bhusaval in Maharashtra in 2023 but the doubling of this Railway Line is hanging fire in the Railway Board. I, therefore, request the Hon'ble Railway Minister to prioritize this railway project based on all necessary inputs, factors, etc., already reckoned with at the appropriate level so that this vital railway project shall usher in a new era of development in this region.

(ends)

**Re: Need to address the stray dog menace in Kerala and other parts of the country**

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I rise today to bring attention to the pressing issue of stray dogs plaguing our nation, particularly in Kerala. The data from Kerala is staggering, with dog bite cases rising consistently over the years: 1,19,191 in 2014, 1,21,693 in 2015, 1,35,217 in 2016, 1,35,749 in 2017, 1,48,899 in 2018, 1,61,055 in 2019, 1,60,483 in 2020, 2,21,379 in 2021, 2,94,032 in 2022, 3,06,427 in 2023, and 3,16,793 in 2024. This year alone, from January to May 2025, 16 deaths have been reported due to dog bites, in these 16, 5 deaths happened after receiving vaccinations. In 2024, there were 26 fatalities, and 25 in 2023. Given the inefficacy of the current Animal Birth Control rules in addressing this issue, I urge the Union Government to reconsider and amend these rules. Moreover, the State Government's plan to allow local bodies to carry out euthanasia of diseased stray dogs is insufficient. I request the Union Government to constitute an expert committee to study legislative measures and best practices, leading to effective legislation to prevent this menace and ensure public safety. Immediate action is crucial to protect the citizens of Kerala and our nation.

(ends)

**Re: Need to enhance the supply of non-subsidised kerosene to Kerala through PDS**

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): With a 590 km coastline, Kerala has about 1.95 lakh active fishermen engaged in sea fishing. It gives livelihood to around 8.04 lakh families. Currently, the fishing community in the State is undergoing a serious existential crisis as there is a considerable reduction in the supply of Kerosene. The traditional fishermen use small fishing boats, which use kerosene as fuel. There are 31,600 registered boats in the State with outboard motors using kerosene. Even though the demand for kerosene is around 51,000 kilolitres, the supply of kerosene in the State under the non-subsidised PDS quota is only 11,640 kilolitres. Since there is a wide gap between the demand and supply of kerosene through PDS, the fishermen are forced to buy kerosene at an exorbitantly high price. This has increased the operational cost of traditional fishing. They are forced to buy it from the open market at INR 105 per litre. Due to this, traditional fishing has become uneconomical, and many fishermen have stopped venturing into the sea. Hence, there is an urgent need to increase the supply of non-subsidized kerosene through PDS. Otherwise, the livelihood security of the traditional fishermen community will be seriously affected. (ends)

**Re: Need to construct a new railway line on Dabla-Khetri-Singhana-Chirawa route in Rajasthan**

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) :** सीकर जिले के डाबला में रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का एक केंद्र है। इस डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर से झुंझुनूं जिले के खेतड़ी, सिंघाना, चिड़ावा जैसे औद्योगिक और व्यापारिक महत्व के क्षेत्र सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। पूर्व में डाबला से खेतड़ी, सिंघाना तक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मीटर गेज रेलवे लाइन थी, जो अब बंद हो चुकी है। यह जमीन रेलवे की है। इसलिए जमीन भी कम अधिग्रहण होगी और इस ट्रैक के लिए दूरी (लंबाई) लगभग 70 किलोमीटर की रहेगी। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देश के नौ मिनी नवरत्न उद्योगों में से एक है। यदि डाबला से खेतड़ी,सिंघाना, चिड़ावा तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाती है,तो इससे न केवल माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सभी क्षेत्रों के लोगों को DFC के लिए सीधा रेल संपर्क मिलेगा। उनको बेहतर परिवहन सुविधा भी उपलब्ध होगी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और अन्य उद्योगों को सस्ता और सुगम परिवहन मिलेगा। साथ ही रेलवे के माल ढुलाई कारोबार में वृद्धि होगी, जिससे सरकार को आर्थिक लाभ मिलेगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि डाबला से खेतड़ी, सिंघाना होते हुए चिड़ावा तक नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु अति शीघ्र सर्वे का कार्य करवाकर रेलवे ट्रैक बिछाने की कृपा करें।

(इति)

**Re: Need to ensure efficient implementation of Centrally-sponsored Fisheries Schemes in Bapatla Parliamentary Constituency**

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): I rise to draw the attention of this House to the persistent gaps in the implementation of central fisheries schemes in the coastal Constituency of Bapatla, Andhra Pradesh, which significantly contributes to India's marine and aquaculture output. Andhra Pradesh contributes 22% of India’s total fish and nearly 70% of shrimp production, making it the top aquaculture State. Despite fisheries contributing 6.72% to agricultural GVA in 2022–23, benefits of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (₹5,945.92 crore sanctioned) and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (₹749.90 crore, including ₹62.83 crore for Andhra Pradesh) remain out of reach for many traditional fisherfolk in Bapatla due to infrastructure gaps and low scheme awareness. I urge the Government to fast-track the development of fishing harbours, landing centres, and cold chain systems in high-output zones enhance awareness through localized campaigns and training on PMMSY benefits—insurance, subsidies, and credit - delivered in local languages; use satellite imagery and AI/ML models to identify infrastructure-deficient fish landing centers, cold chain gaps, and unserviced fisher villages within a 15 km coastal buffer. Therefore, immediate intervention is essential to address local distress, enhance fisher welfare, and strengthen India’s blue economy vision.

(ends)

**Re: Likely ecological damage due to rehabilitation of project affected persons by proposed use of salt-pan land in Mulund, Bhandup and Vikhroli areas in Maharashtra**

SHRI SANJAY DINA PATIL (MUMBAI NORTH-EAST): I wish to bring to the attention of this House a deeply concerning development in my Parliamentary Constituency — the proposed use of 255.6 acres of salt-pan land in the Mulund, Bhandup, and Vikhroli areas for rehabilitation of project affected persons. While the Bombay High Court may have approved this plan, the ground reality is alarming. There is no sewerage network, no drainage system, and no assured water supply. There has been no Environmental Impact Assessment, and CRZ clearance is missing. Yet, thousands of families are set to be relocated here. These salt pans are not just empty land — they are natural flood buffers and crucial for groundwater recharge. Reckless redevelopment without infrastructure or environmental planning will lead to flooding, health hazards, and long-term ecological damage. Rehabilitation must be carried out with care, planning, and dignity. I strongly urge the Government to pause this project and ensure that proper civic infrastructure, environmental clearances, and long-term safeguards are put in place before any resettlement begins.

(ends)

**Re: Need to establish a Trauma Care Centre in AIIMS, Mangalagiri in Andhra Pradesh**

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): The speedy progress of various works being done at AIIMS, Mangalagiri, is appreciable. And, achieving 25 lakh outpatient consultations clearly indicate the rapidly gaining popularity of AIIMS, Mangalagiri. I wish that the same trend be continued in inpatient services as well and excel in academics and ultimately achieve the objective of making AIIMS, Mangalagiri, an institute of national importance. It is welcome that the Government has opened many departments and created many facilities in AIIMS, Mangalagir. But, Trauma Centre has not been set up which, I strongly feel, is very critical and important since this institute is very near to National Highway and many road accidents taking place in this area. So, Trauma Centre is the need of the hour. Hence I appeal to the hon. Prime Minister and hon. Health Minister to kindly ensure that Trauma Care Centre is set up at AIIMS, Mangalagiri as early as possible.

(ends)

**Re: Need to address the issue of land subsidence caused by Coal mine blasts in Jharkhand**

**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) :** केशलपुर कुम्हार बस्ती,केशलपुर मुंडा धौड़ा,पूर्वी बसुरिया में चार-पाँच माह से बस्ती के बगल में बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र स०4 के आउटसोर्सिंग परियोजना विस्तार से भू-धसान हो रही है जिससे ग्रामीणों का जीवन खतरे में है एवं ग्रामीणों को शीघ्र विस्थापित कर पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था करना आवश्यक है। ख़ान सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर परियोजना विस्तार,तय मानकों से ज़्यादा हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यह सूचित कर रहा हूँ की इन जगहों पर खुले आम कोयला चोरी भी हो रही है जहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।मेरे बार बार सचेत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसका परिणाम है कि 22 जुलाई, 2025 को वहाँ चाल धंस गयी और 5 लोगों उसमे समा गए।ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले रामगढ़ में हुई थी जिसमे 4 लोगों की जान गयी थी। यहाँ तो अमानवीय ढंग से बचाव कार्य भी एक दिन बाद शुरू की गयी।मेरे बार बार सचेत करने के बाद भी प्रबंधन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और कोयला मंत्रालय भी ऐसी घटना को गंभीरता से नहीं लेता जिसका नतीजा है की एक माह मे 10 जान चली गयी।

(इति)

**Re: Need to expedite work on six laning of Pune-Kolhapur National Highway in Maharashtra**

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I wish to draw the urgent attention of the Government to the inordinate delay in the six-laning of the crucial Pune-Kolhapur National Highway. Despite being underway for over two years, the project's progress, particularly on the Pune to Satara stretch, has been distressingly sluggish. This has resulted in a significant increase in travel time for commuters heading towards Satara, Sangli, and Kolhapur. This severely impacts my constituents in the Sangli Lok Sabha, throttling economic activity and causing great hardship to farmers reliant on this route for market access. The current condition of the road is deplorable, with vast sections being unsafe for travel. Critical work, such as the construction of underpasses, remains pending, posing a constant risk to the safety of pedestrians and local residents. It is a matter of great concern that despite the slow pace and incomplete nature of the project, contractors are being permitted to collect full tolls from the public. This is an unjust burden on the citizens who are already suffering from the poor road conditions and extended travel times. I, therefore, urge the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways to intervene in this matter, expedite the construction work, ensure the immediate repair of the existing road, and suspend toll collection until the project is substantially completed.

(ends)

**Re: Need to reopen the schools closed down in Sambhal district of Uttar Pradesh**

**श्री जिया उर रहमान (सम्भल) :** उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले में हाल ही में 181 प्राथमिक विद्यालय या तो बंद कर दिए गए या अन्य स्कूलों में मिला दिए गए। इनमें 95 स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए और 86 स्कूलों का मर्जर नजदीकी विद्यालयों में किया गया। यह फैसला उन स्कूलों पर आधारित था जहाँ छात्रों की संख्या 50 से कम थी। लेकिन इसका असर सीधे बच्चों पर पड़ा है जिन्हें अब दूर-दराज़ स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे ड्रॉपआउट बढ़ने की संभावना है और सैकड़ों शिक्षक सरप्लस घोषित कर दिए गए हैं। यह केवल सम्भल की बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद या मर्ज किए जा चुके हैं। यह निर्णय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (Right to Education - RTE) अधिनियम की भावना के खिलाफ है, जिसमें हर बच्चे को उसके घर के पास शिक्षा उपलब्ध कराने की बात है। इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार में रुकावट पैदा हो रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि RTE का पूरी तरह पालन हो और इन बंद किए गए विद्यालयों को फिर से खोला जाए, ताकि गाँवों और छोटे कस्बों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। (इति)

**جناب ضیاءالرحمان (سنبھل): محترم چیرمین صاحب، اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں ابھی حال ہی میں 181 پرائمری اسکول یا تو بند کر دئے گئے یا دوسرے اسکولوں میں ملا دئیے گئے۔ ان میں 95 اسکول پوری طرح بند کر دئے گئے اور 86 اسکولوں کا مرجر نذدیکی اسکولوں میں کیا گیا۔ یہ فیصلہ ان اسکولوں پر آدھارِت تھا جہاں طلباء کی تعداد 50 سے کم تھی۔ لیکن اس کا اثر سیدھے بچوں پر پڑا ہے جنہیں اب دور دراز اسکولوں میں جانا پڑےگا، جس سے ڈراپ آؤٹ کی شرح میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اور سینکڑوں اساتذہ کو فاضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف سنبھل کی بات نہیں ہے۔ اب تک پورے اتر پردیش میں تقریباً 26,000 پرائمری اسکولوں کو بند یا ضم کردیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ مفت اور لازمی تعلیم کے حق (آر ٹی ای) ایکٹ کی روح کے خلاف ہے، جو ہر بچے کو اس کے گھر کے قریب تعلیم فراہم کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس سے بچوں کے تعلیم کے بنیادی حق میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔**

**میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آر ٹی ای کے مکمل نفاذ کو یقینی بنائے اور ان بند اسکولوں کو دوبارہ کھولے تاکہ دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جاسکے۔ شکریہ ۔۔**

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I would request you to go back to your own seats.

… (*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** मैं सभी सदस्यों ने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइए, तभी हम कार्यवाही आगे लेकर जा सकते हैं। ऐसे नहीं होगा। आप सब अपनी-अपनी सीट पर बैठिए।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, गोवा के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बिल बहुत दिनों से पेन्डिंग चल रहा है। मैंने खुद आपसे दो बार रिक्वेस्ट की है, मैंने आप सबसे गोवा के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बिल को डिसकस करने के बारे में दो बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन इस पर अभी तक डिसकशन नहीं हुआ।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Are we trying to show our love for the STs in the country? This Bill is pending for that.

… (*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** बहुत दिनों से यह बिल पेन्डिंग चल रहा है। आप सभी के शून्यकाल का भी विषय है।

… (व्यवधान)

**विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सर, आपने गोवा की बात की, … (व्यवधान) लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नम्बर 8 पर कन्सीडरेशन एंड पासिंग के लिए यह बिल लगा हुआ है। … (व्यवधान) The Readjustment of Representation for Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024 … (*Interruptions*)

गोवा में जो एसटी पॉपुलेशन है, उसकी सीटें बढ़ाने से संबंधित यह बिल है। ... (व्यवधान) इसका मतलब अपोजिशन के लोग एसटी के खिलाफ भी हैं। ये चर्चा करना नहीं चाहते हैं। गोवा में एसटी की सीटें बढ़ने वाली हैं,... (व्यवधान)

अभी वहां सीटें नहीं हैं। ... (व्यवधान) इस बिल के माध्यम से गोवा असेम्बली में अनुसूचित जनजातियों की सीटें बढ़ने वाली हैं। क्या ये इसके खिलाफ भी हैं? ... (व्यवधान) इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं?

यह इतना महत्वपूर्ण बिल है। ... (व्यवधान) गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, उसके लिए यह बिल है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। हम गोवा के अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जहां अभी कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। यह रिप्रेजेन्टेशन देने के लिए एक ऑपर्च्युनिटी है।

... (<u>व्यवधान</u>)

**माननीय सभापति:** क्या आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों को रिप्रेजेन्टेशन मिले?

... (<u>व्यवधान</u>)

**माननीय सभापति:** सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1409 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 अगस्त 2025 / 13 श्रावण, 1947 (शक)</u>

<u>के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>